(ख) इन रिक्त स्थानों को न भरे जाने के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक भर दिए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृत पद संख्या एक अध्यक्ष और 10 सदस्य की है जिनमें से सदस्यों के दो पद क्रमशः दिनांक 13-5-1988 और 24-5-1988 से रिक्त पड़े हैं ।

(ख) इन रिक्तियों को भरने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा मिलावटी दवाओं का उत्पादन

682. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, पटना, झांसी और कानपुर द्वारा निर्मित दवाओं में बड़े पैमाने पर मिलावट की जाती है और वे अपने गुप्त लिखित फार्मूले के बजाए घटिया किस्म की वस्तुएं मिला कर दवाएं तैयार करते हैं जिनका रोगियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार उनके द्वारा तैयार की जाने वाली दवाओं में अक्सर मिलाए जाने वाली घटिया किस्म की सामग्री को जब्त करने का विचार रखती है ; और

(ग) क्या सरकार राज्यों की राजधानियों में ऐसे रासायनिक जांच केन्द्र खोलने का विचार रखती है जहां पर उपभोक्ता दवाओं की शुद्धता और उपयोगिता की जांच करा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति की फार्मेसियों पर नियंत्रण और उनका निरीक्षण, निर्माण लाइसेंस जारी करने का कार्य राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त राज्य औषध नियंत्रकों का है । इस मंत्रालय के किसी भी राज्य औषध नियंत्रक द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति से वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा अपने गुप्त लिखित फार्मूले की बजाए घटिया किस्म की वस्तुयें मिलाकर आयुर्वेदिक दवाएं तैयार करने के बारे में जिनका रोगियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधों के परीक्षण के लिए गाजियाबाद में एक भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाल स्थापित की है। राज्यों की राजधानियों में ऐसी प्रयोगशालाएं खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

Resistance against launching of Agni Missile

683. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item which appeared in the 'Newstime' of April 18, 1989, to the effect that there was resistance on the part of the people of eleven villages who come within the safety zone of the Interim Testing Range (ITR) at Chandipur in Orissa for launching of MRBM "Agni" on full moon day between April 20, and May 10, 1989;

(b) if so, whether it is also a fact that they have been threatened of forceful eviction; and

(c) what has been the consequence of such a resistance and threat of evacuation?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) For the AGNI launch planned for 20 April, 19 89, the villagers were shifted temporarily outside the safety zone and no resistance from these people was observed.

Projections made by the Planning Commission for Textiles Industry

684. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) what were the projections made by the Planning Commission for the textile industry, sector-wise, during the last two five-year plans and what are the projections envisaged/proposed for the 8th Five Year Plan;

(b) whether the Planning Commission have set up a Working group on textiles, as reported in 'Navbharat Times' dated the 4th April, 1989; if so, the terms of reference and names/addresses of its members;

(c) what are the titles, brief contents of reports and studies on textiles conducted by/for the Planning Commission during the last five years on any sector of the textiles industry; and

(d) what are the titles, brief contents of reports and studies on textiles done by other Government or non-Government agencies, which shed light on the status, growth, problems or changes in different sectors of the textiles complex?

THE MINISTER OF PLANNING AND THE MINISTER OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI MADHABSINH SOLANKI): (a) A Statement I indicating the projections made by the Planning Commission for the Textile Industry sector-wise during the 6th and 7th Five Year Plans is enclosed (*See* below). Projections for the 8th Five Year Plan have not yet been finalised.

(b) The Planning Commission has set up a Working Group to formulate the development programme for textile industry for the 8th Five Year Plan under the Chairmanship of Secretary (Textiles), Ministry of Textiles. A copy of the term of Reference and names/addresses of the members of the Working Group is enclosed as Statement-II (*See* below).

(c) and (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Statement-I

The projections made by the Planning Commission for Textile Industry sector-wise during the 6th and 7th Five Year Plan

SIXTH PLAN TARGETS

CLOTH

(in million metres)

Sector	Total
Mill	4900
Powerloom	4300
Handloom	4100
TOTAL	13300

SEVENTH PLAN TARGETS

CLOTH

(in million metres)

Sector	Total
Mill	4500
Powerloom	5400
Handloom	4600
TOTAL	14500